शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 3 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 16 – 23 जनवरी 2023 मूल्य पांच रूपए

लाभ के पद के दायरे से बाहर हैं

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बने विधायक

क्या सुक्खू सरकार सही में व्यवस्था बदल पायेगी

हर नियुक्ति कैबिनेट रैंक में होने से उठी चर्चा

राजस्व व्यय नियंत्रित करने के केन्द्र के सितम्बर 2020 के निर्देशों पर उठी चर्चा

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसम्बर को शपथ ग्रहण की थी। इन्हीं के साथ उप – मुख्यमन्त्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी शपथ ग्रहण की थी और तभी से यह दो लोगों की सरकार अपने काम में जुट गयी। लेकिन इस सरकार को अपना मन्त्रीमण्डल विस्तार करने में एक माह से भी ज्यादा का समय लग गया। पहले ही मन्त्रीमण्डल विस्तार में मन्त्रीयों के तीन पद खाली रखने पड़ गये और विस्तार से पहले ही छ: मुख्य संसदीय सचिवों की शपथ दिलानी पड़ी। किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिये पार्टी के भीतर और बाहर की स्थितियों को समझने के लिये यह एक पर्याप्त आधार बन जाता है। क्योंकि इसी कड़ी के विस्तार में कांग्रेस के विधायक आर. एस.बाली को पर्यटन विकास निगम का कैबिनेट रैंक में अध्यक्ष बनाना पड़ा है। हिमाचल के एक्ट के मुताबिक ऐसी नियुक्तियां पाने वाले विधायक लाभ के पद के दायरे से बाहर हैं। इसलिये देर सवेर कुछ और विधायकों को भी ऐसी ही नियुक्तियों से नवाजना पड़ जाये तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी।

मुख्यमन्त्री ने शपथ लेने के बाद अपने पहले ही ब्यान में यह कहा था कि वह राजनीति करने नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने आये हैं। मुख्यमन्त्री के इस ब्यान का स्वागत हुआ था। लेकिन इस ब्यान के बाद जो पहला बड़ा फैसला आया उसमें पिछली जयराम सरकार द्वारा अंतिम छ: माह में लिये गये फैसलों को पलटते हुये इस दौरान खोले गये नौ सौ संस्थानों को बन्द करने के फैसले हर रोज आने लग गये। इन्हीं फैसलों के दौरान 31 दिसम्बर को मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति का समय आ गया। प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली चला आ रहा था। इस पद को नेता प्रतिपक्ष की चयन में भागीदारी के बिना भरा नहीं जा सकता था। इसलिये प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से ही विधायकों की शपथ से पहले ही नेता प्रतिपक्ष का चयन हो गया और पूर्व मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर इस पद के लिए चुन लिये गये। इस चयन के बाद मुख्य सूचना आयुक्त का चयन हुआ। पूर्व मुख्यसचिव आर. डी.धीमान इस पद के लिये चुने गये। इसी कड़ी में चार बैच जूनियर प्रबोध सक्सेना को मुख्य सचिव बना दिया गया। सुक्खू सरकार ने जयराम द्वारा लिये गये जिन फैसलों को पलटा है उनको लेने में तत्कालीन मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की कितनी सक्रिय भूमिका रही है इसका खुलासा इस संद्धर्भ में भाजपा नेताओं सुरेश कश्यप और विक्रम ठाकुर द्वारा प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर हुई याचिकाओं से सामने आ जाता है। सरकार के इन फैसलों से यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या इस तरह व्यवस्था बदली जा सकेगी या अनचाहे ही यह सरकार भी उसी व्यवस्था के ट्रैप में फंसती जा रही है।

यह सवाल और आशंकाएं इसलिये प्रसांगिक हो जाती हैं क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। बतौर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जयराम सरकार से लिखित में वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र की मांग कर चुके हैं। अब नई विधानसभा के धर्मशाला में आयोजित हुये पहले ही सत्र में सुक्खू सरकार पिछली जयराम सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगा चुकी है। स्वयं मुख्यमन्त्री सुक्खू एक पत्रकार वार्ता में पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई करीब ग्यारह हजार करोड़ की देनदारियों की बात कर चुके हैं। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक इसी वित्तीय वर्ष का कर्ज दस हजार करोड़ से ऊपर चला जायेगा। ऐसी वित्तीय परिस्थिति के परिदृश्य में आज जो फैसले और घोषणाएं सुक्खू सरकार कर रही है क्या उनके पूरा होने पर स्वत: ही प्रश्नचिन्ह नहीं लग जाते हैं? आज सरकार को गारन्टीयां पूरी करने के लिये कर्ज लेने या कर लगाने के अतिरिक्त और कौन से साधन शेष बचे हैं। यह स्थिति उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब राजनीतिक संतुलन बनाये रखने के लिये हर राजनीतिक नियुक्ति कैबिनेट रैंक में ही करने की बाध्यता बन जाये। क्योंकि यह तय है कि जब मोदी की केन्द्रीय सरकार जयराम को ही घोषणाओं के अतिरिक्त व्यवहारिक रूप से कोई आर्थिक मदद नहीं दे पायी है तो सुक्खू सरकार को भी कुछ नहीं दे पायेगी। केंद्र सरकार ने 4 सितम्बर 2020 को ही राजस्व खर्च को नियंत्रित करने के लिये केन्द्र के सचिवों से लेकर राज्य सरकारों त्तक को निर्देश जारी कर रखे हैं। इन निर्देशों की न तो अनुपालना ही हुई है और न ही अवहेलना के लिये कोई दण्डित हुआ है।

यह है संबंधित अधिनियम

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1971

An Act to declare certain offices of profit under the Government of India, or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution not to disqualify their holders for being chosen as, or for being, members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

Prevention of disqualifications for membership of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh.- A person shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds any of the following offices of profit under the Government of India or the Government of any State:-

(a) the office of the Deputy Minister or Minister of State;

(b) any office held by a Minister, Minister of State, or DeputyMinister whether *ex-officio* or by name;

1 [(b-a) the office of the Political Advisor to the Chief Minister;]

(c) the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly or of Parliament or of the Legislative Assembly of any other State;

(d) the office of the Chief Parliamentary Secretary or Parliamentary Secretary;

(e) the office of the Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in any Legislative Assembly or in Parliament;

(f) the office of village revenue officer whether called a lamberdar, malguzar, patel, deshmukh or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who is remunerated by a share of or commission on, the amount of land revenue collected by him, but who does not discharge any police functions;

(g) any office in the National Cadet Corps, the Territorial Army, the Air Defence Reserve and the Auxiliary Air Force under any law for the time being in force;

(h) the office of a member of a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State;

(i) the office of Chairman or member of the Syndicate, Senate, Executive Committee, Council or Court of a University or any other body connected with a University;

(j) the office of the Vice-Chancellor of any University;

[j-a) the office of the Chairman or Vice-Chairman of any statutory or non-statutory body, where the power to make the appointment or power to remove the person from the office is vested in the State Government;]

(k) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government of India or the Government of any State or sent outside the State of Himachal Pradesh by the Government of the said State for any special purpose;

(l) the office of chairman or member of a committee (whether consisting of one or more members) set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(m) the office of [1] [XXXXXXX] director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (l) if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(n) the office of any honorary medical officer or honorary assistant medical officer in a hospital under Government management;

(o) a person drawing his service pension, political pension or grant, mansab, charitable grant or commutation sum of compensation in respect of a jagir, inam or other grant;

(p) the office of an agent or other like office for the purpose of effecting sales of or collecting subscription towards, National Plan Certificates or any other savings certificates or Government securities notified as such by the Central Government for such commission as the Central Government may have fixed in that behalf or without such commission;

(q) the office of an examiner for any examination held by the Central or State Government or by the Union Public Service Commission or any State Public Service Commission;

(r) the office of Sarpanch or member of a Panchayat under any law for the time being in force [2] [;]

[3][(s) notwithstanding anything contained in clauses (l) and (m) of this section, the office of [4][the Chairman, Vice-Chairman or] member of Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes appointed by the Government of India [5] [or the office of the Deputy Chairman of the Himachal Pradesh State Planning Board constituted by the State Government.]

संत रविदास की शिक्षाएं वर्तमान परिपेक्ष्य में और भी प्रासंगिकःराज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि संत गुरू रविदास जी किसी एक समुदाय से सम्बंधित नहीं थे बल्कि उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता के लिए थी जोकि आज

प्रासंगिक हैं। उन्होंने लोगों से भेदभाव मुक्त समाज के निर्माण के लिए संत रविदास की शिक्षाओं का पालन करने का आग्रह किया।

राज्यपाल ऊना के संतोषगढ़ के प्रसिद्ध जोड़ मेला में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जोड़ मेला ऐतिहासिक है जिसका इतिहास संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि वह सभी व्यक्ति जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया है वह सभी के लिए सम्मानीय हैं। उन्होंने मंदिर समिति से आहवान किया कि वह इस संघर्ष की कहानी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को जान सकें।

राज्यपाल ने कहा कि संत रविदास ने जीवन भर समाज में भेदभाव को दूर करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने पूरे समाज को एकजुट होने की शिक्षा दी। उन्होंने जिन विषयों को समाज के सामने रखा, वह समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं हमें एक साथ रह कर एक आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती हैं।

उन्होंने कहा कि संत रविदास के विचार राष्ट्र के लिए हैं और वह राष्ट्रीय संत हैं। उनकी शिक्षाओं को जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर मंदिर निर्माण के संघर्ष काल में जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने संत रविदास जोड़ मेला के संस्थापक शिंगारा राम संगुड़ा के परिजनों को भी सम्मानित किया।

इससे पूर्व राज्यपाल ने संत रविदास के मंदिर में माथा टेका।

गुरू रविदास जोड़ मेला समिति के अध्यक्ष बलवंत सिंह ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया।

विधायक सतपाल सत्ती ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, समन्वयक मेला समिति बलवीर बग्गा, प्रभारी मेला समिति कुंवर जागीर संगुड़ा, प्रधान संत रविदास धार्मिक सभा संतोषगढ़ बलवीर सिंह, आद धर्म मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत हीरा दास और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति से भेंट

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली में मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति के साथ यह उनकी पहली मुलाकात है।

मुख्यमंत्री की उपराष्ट्रपति से भेंट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की।

यह एक शिष्टाचार भेंट थी। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति के साथ यह उनकी पहली मुलाकात है।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि समाज के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है और भावी

पीढ़ियों को ज्ञान आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान करने से राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई जा सकती है।

राज्यपाल ने यह बात ऊना जिला स्थित धुसाड़ा कैम्ब्रिज इंटरनैशनल स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कही।

राज्यपाल ने कहा कि आगामी 25 वर्ष देश की भावी पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने इन 25 वर्षों को अमृतकाल की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों के उपरांत देश का भविष्य क्या होगा, वर्तमान में इस बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकता है ताकि हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सकारात्मक दिशा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। उन्होंने स्कूल प्रबन्धन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय आत्मसंस्कृति, परम्परा तथा स्वदेशी की भावना को जागृत करने का है और नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया।

कैम्ब्रिज इंटरनैशनल स्कूल पुणे के निदेशक राम डी. रैणा ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया और स्कूल की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया।

चिन्तपूर्णह्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, कैम्ब्रिज इंटरनैशनल स्कूल की अध्यक्षा सीमा तनेजा, स्कूल के निदेशक संदीप पराशर, कैम्ब्रिज इंटरनैशनल स्कूल पुणे के अध्यक्ष धनंजय वारनेकर, स्कूल की सचिव पूनम पराशर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने जिज्ञासा बहल के स्टार्ट-अप की सराहना की

शिमला/शैल। शिमला जिला की निवासी जिज्ञासा बहल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष अपने स्टार्ट-अप के अंतर्गत गृह सज्जा एवं जीवनशैली से सम्बंधित उत्पादों का प्रदर्शन किया। इन सभी उत्पादों का निर्माण कुल्लू पट्टी पर आधारित है जो आधुनिकता और परम्परा का अनूठा सम्मिश्रण है।

मुख्यमंत्री ने जिज्ञासा बहल के प्रयासों की सराहना करते हुए इन उत्पादों के प्रति गहरी रूचि दिखाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हस्तशिल्प परम्परा को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण पर विशेष बल दे रही है। मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर तथा प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नौणी विवि से अब तक 1.50 लाख से अधिक शीतोष्ण फल पौधों की बिक्री

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी द्वारा शीतोष्ण फलों की रोपण सामग्री की वार्षिक बिक्री में अब तक सेब, कीवी, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, प्लम, अखरोट आदि जैसे फलों की विभिन्न किस्मों के 1.50 लाख से अधिक पौधों की बिक्री हो चुकी है।

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों समेत उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर आदि राज्यों के किसानों ने विश्वविद्यालय की विभिन्न नर्सरी से फलों के पौधे खरीदे हैं। इस वर्ष वार्षिक बिक्री 4 जनवरी से पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर नौणी के मुख्य परिसर में स्थित फल विज्ञान विभाग, बीज विज्ञान विभाग और मॉडल फार्म, और कृषि विज्ञान केंद्र सोलन, केवीके चंबा, केवीके रोहड़ू, आरएचआरटीएस मशोबरा, कुल्लू के बजौरा, किन्नौर के शारबो में स्तिथ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों और औदयानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी में शुरू हुई थी।

जहां केवीके चंबा और शारबो केंद्र में उपलब्ध सभी प्लांट बिक चुके हैं, वहीं यूनिवर्सिटी के विभिन्न केंद्रों के बाकी प्लांट्स की बिक्री आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर और क्षेत्रीय केन्द्रों में अभी भी सेब और गुठलीदार फलों की कई किस्में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मुख्य परिसर में फल विज्ञान विभाग और बीज विज्ञान विभाग में विभिन्न क्लोनल रूटस्टॉक्स पर सेब के पौधे उपलब्ध हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

विधायक प्राथमिकता बैठकों की आयोजन तिथि में परिवर्तन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2023-24 के लिए विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए प्रस्तावित दो दिवसीय बैठकों की आयोजन तिथि में आंशिक परिवर्तन किया गया है। यह बैठकें अब 01 व 02 फरवरी, 2023 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित की जाएंगी।

01 फरवरी, 2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.30 बजे तक चम्बा, शिमला और लाहौल-स्पीति तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

02 फरवरी, 2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.30 बजे तक कांगड़ा व किन्नौर जिलों तथा अपराह्न 2 से 5 बजे तक सोलन, बिलासपुर तथा मण्डी के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

इन बैठकों में वार्षिक बजट 2023-24 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठकों में विधायकों से वर्ष 2023-24 के लिए मित्तव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी।

सरकार औद्योगिक नीति में बदलाव लाने पर कर रही विचारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) हिमाचल इकाई के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता और उपाध्यक्ष गगन कपूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में समर्पित निवेश एवं सुगमता ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे अनुमोदन और स्वीकृतियां समयबद्ध प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में निवेश की गति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रयास हिमाचल प्रदेश को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, आईटी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस), बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए प्रस्तावित निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो के पास 10 करोड़ रुपये से अधिक की क्षमता की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और स्वीकृति देने की शक्तियां निहित होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों की समस्याओं से अवगत है। उन्होंने उद्योगपतियों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रेल संपर्क के अलावा सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट बनाकर हवाई संपर्क को मजबूत किया जा रहा है तथा प्रमुख सड़कों को फोरलेन बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार औद्योगिक नीति में आवश्यक बदलाव लाने पर विचार रही है। हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए प्रदेश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने उद्योगों से इस क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार किसानों से बेहतर कीमत पर गाय और भैंस का दूध खरीदकर डेयरी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी।

सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने राज्य में समर्पित निवेश एवं सुगमता ब्यूरो स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव की सराहना की। सीआईआई हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष गगन कपूर और अन्य प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर अपनी विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सेवा भाव तथा समर्पण से काम करें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीःस्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग का कार्य मानवता और करुणा से जुड़ा होने के कारण विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को सेवा भाव तथा समर्पण से अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। यह उद्गार स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ (कर्नल) धनी राम शांडिल ने शाहपुर के नागरिक अस्पताल में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। स्वास्थ्य मंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हर वर्ग के लोगों को सुगमता से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने को ओर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के अपने इस प्रवास के दौरान उन्हें यह भी बताया गया है कि कई संस्थानों में ओटीए (ऑपरेशन थियेटर सहायक) के पद रिक्त चल रहे हैं इस बारे भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों को हॉस्पिटल कैम्पस में ही रहने की सुविधा मिल सके इस तरह के प्रयास भी चरणबद्ध तरीके से किये जायेंगें ताकि मरीजों को त्वरित इलाज की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा ताकि दूर-दराज के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और गरीब से गरीब नागरिक भी अपना इलाज अच्छे ढंग से करवा सके।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया ने स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया तथा शाहपुर में आने पर उनका आभार जताया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं बारे विस्तृत जानकारी दी।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्थानीय विधायक केवल पठानिया को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखी गई माँगों की शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

इससे पूर्व रैत में सैनिक लीग शाहपुर के सदस्यों ने मंत्री के साथ बैठक भी की और अपनी विभिन्न माँगें उनके समक्ष रखी। सैनिक लीग ने डेंटल चेयर, ईसीएचएस, सैनिक विश्राम गृह निर्माण इत्यादि विषयों को मंत्री के सम्मुख रखा। मंत्री ने बड़ी ही गंभीरता और सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों को सुना और उचित निदान की बात कही।

बागवानी मंत्री के अधिकारियों को निर्देश वर्तमान कार्यप्रणाली में लाएं सुधार

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सेब के लिए जाना जाता है तथा फल उत्पादन प्रदेश के बागवानों की आय का मुख्य स्रोत है। प्रदेश सरकार बागवानों की आय बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रही है। प्रदेश में सेब के अतिरिक्त अन्य फलों के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बागवानी मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बागवानों तथा फील्ड अधिकारियों के सुझावों पर विचार कर वर्तमान कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। उन्होंने ऑफिस टू ऑर्चर्ड कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने पर बल दिया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग द्वारा प्रदेश उष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य वर्धन परियोजना (एचपी शिवा) के तहत किए गए कार्यों की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित एचपी शिवा की सफलता के परिणामस्वरूप प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है।

सचिव उद्यान अमिताभ अवस्थी ने इस अवसर पर उद्यान मंत्री का स्वागत करते हुए विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

निदेशक उद्यान विभाग डॉ. आर. के. पूर्थी ने कहा कि विभाग प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक हरीश जनारथा, कुलदीप राठौर तथा पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

इस अवसर पर एचपी शिवा के परियोजना निदेशक देवेन्द्र ठाकुर, बागवानी विकास परियोजना के परियोजना निदेशक सुदेश कुमार मोख्टा और उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने विभाग के कार्यों की समीक्षा की

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विभाग की कार्यप्रणाली और विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अनिरुद्ध सिंह ने अधिकारियों को विभाग की सभी योजनाओं का लाभ आमजन को सुनिश्चित करने के लिए दक्षता व समयबद्धता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता और सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि विभाग जमीनी स्तर पर कार्य कर सरकार की अनेक योजनाओं को कार्यान्वित करता है, इसलिए विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का दायित्व है कि वह अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के लिए योजना तैयार करें।

उन्होंनें आश्वासन दिया कि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र उचित समाधान किया जाएगा।

निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ऋगवेद ठाकुर ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का स्वागत किया तथा विभाग की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

बैठक में सचिव पंचायती राज प्रियतु मंडल, अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज केवल शर्मा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीमेंट प्लांट को क्रियाशील बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताःउद्योग मंत्री

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ट्रक ऑपरेटर यूनियन बरमाणा एवं दाड़लाघाट और सीमेंट कंपनी प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन और सीमेंट कंपनी प्रबंधन के बीच आम सहमति बनाना है, ताकि सीमेंट संयंत्र अपना संचालन फिर से सुचारू रूप से शुरू कर सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी प्रबंधन और उसके मालिकों से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और इन संयंत्रों का जल्द से जल्द क्रियाशील करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, इसके अलावा ट्रक संचालक एक महीने से भी अधिक समय से बिना काम के हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से जुड़े हुए हैं, वह अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि दोनों ही पक्ष आपसी सहमति से कार्य करना आरम्भ करें और उन्होंने इस संबंध में सहयोग का आश्वासन दिया है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि बैठक में हुई चर्चा तथा सार्थक परिणाम के बारे में शीघ्र ही मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के.सी. चमन, निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति, निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम अनुपम कश्यप, ट्रक अपरेटर व अदानी कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

जीवन का रास्ता स्वयं बना बनाया नहीं मिलता इसे बनाना पड़ता है जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है।
– स्वामी विवेकानंद –

सम्पादकीय

जन अपेक्षाओं के आईने में भारत जोड़ो यात्रा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीन हजार आठ सौ किलोमीटर का सफर करीब पांच माह में पूरा करके पूर्ण होने जा रही है। आज की परिस्थितियों में यदि कोई राजनेता इस तरह की यात्रा का संकल्प लेकर उसे पूरा करके दिखा दे तो निश्चित रूप में यह मानना पड़ेगा कि उस नेता में कुछ तो ऐसा है जो उसे दूसरे समकक्षों से कहीं अलग पहचान देता है। इस यात्रा को यदि तपस्या का नाम दिया जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि पांच माह तक हर रोज करीब पचीस किलोमीटर पैदल चलना और रास्ते में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से संवाद स्थापित करना तथा मीडिया से भी आमने-सामने होना कोई आसान काम नहीं है। राहुल गांधी के इस इतिहास को कोई दूसरा नेता लांघ सकेगा ऐसा नहीं लगता। इतनी लम्बी यात्रा में बिना थकान, शान्त बने रहकर समाज के हर वर्ग की बात सुनना, उसे राष्ट्रीय प्रश्नों के प्रति जागरूक करना अपने में ही एक बड़ा स्वाध्याय और सीख हो जाता है। पांच माह में यह यात्रा बारह राज्यों और दो केन्द्र शासित राज्यों से होकर गुजरी है। एक सौ उन्नीस सहयात्रियों के साथ शुरू हुई इस यात्रा में रास्ते में कैसे हजारों लाखों लोग जुड़ते चले गये वही इस यात्रा को एक तपस्या की संज्ञा दे देता है। इसी से यह यात्रा अनुभव और ज्ञान दोनों का पर्याय बन जाती है। राहुल ने स्वयं इस यात्रा को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान करार दिया है।

राहुल एक सांसद हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इस नाते देश की जनता के प्रति उनकी एक निश्चित जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के नाते देश की समस्याओं को आम जनता के सामने रखना और उन पर जनता की जानकारी और प्रतिक्रिया को जानना एक आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। इन समस्याओं पर जनता से सीधा संपर्क बनाना उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब लोकतांत्रिक मंच संसद और मीडिया में ऐसा करना कठिन हो गया हो। देश जानता है कि आज प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय समस्याओं पर जनता से सार्थक संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मन की बात में अपनी ही बात जनता को सुनायी जा रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है उसे सुनने का कोई मंच नहीं है। यहां तक की पिछले आठ वर्षों में मीडिया से भी खुले रुप में कोई संवाद नहीं हो पाया है। यही कारण है कि नोटबन्दी पर आम आदमी का अनुभव क्या रहा है उसकी कोई सीधी जानकारी प्रधानमन्त्री को नहीं मिल पायी है। जीएसटी का छोटे दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़ा है और जीएसटी के करोड़ों के घपले क्यों हो रहे हैं। कोविड में आपदा को किन बड़े लोगों ने अवसर बनाया और ताली-थाली बजाने तथा दीपक जलाने पर आम आदमी की प्रतिक्रिया क्या रही है? आज सर्वोच्च न्यायालय में सरकार को शपथ पत्र देकर बार-बार यह क्यों कहना पड़ा है कि वैक्सीनेशन ऐच्छिक थी अनिवार्य नहीं? इसके प्रभावों/ कुप्रभावों की जानकारी रखना वैक्सीनेशन लेने वाले की जिम्मेदारी थी।

अन्ना आन्दोलन में जो लोकपाल की नियुक्ति जन मुद्दा बन गयी थी उसकी व्यवहारिक स्थिति आज क्या है। 2014 के चुनावों में हर भारतीय के खाते में पंद्रह लाख आने का वादा जुमला क्यों बन गया। सार्वजनिक बैंकों से लाखों करोड़ का कर्ज लेकर भाग जाने वालों के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कारवाई क्यों नहीं हुई। जब चीन के साथ रिश्ते सौहार्दपूर्ण नहीं है तो फिर उसके साथ व्यापार लगातार क्यों बढ़ रहा है। दो करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा न होने पर देश के युवा की प्रतिक्रिया क्या है? महंगाई से आम आदमी कैसे लगातार पीड़ित होता जा रहा है? आज के इन राष्ट्रीय प्रश्नों पर दुर्भाग्य से प्रधानमन्त्री या उनके किसी दूसरे निकट सहयोगी का जनता से सीधा संवाद नहीं रह गया है। इस वस्तुस्थिति में आज देश को एक ऐसे राजनेता की आवश्यकता है जो जनता के बीच जाकर उससे सीधा संवाद बनाने का साहस दिखाये। राहुल गांधी ने पांच माह में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर एक संवाद स्थापित किया है जो उनका कोई भी समकक्ष नहीं कर पाया है। इसलिये यह उम्मीद की जानी चाहिये कि वह जन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

आईएएमसी की भारत विरोधी षड्यंत्र का पर्दाफाश

गौतम चौधरी

संयुक्त राज्य अमेरिका में जब से जो बिडेन की सरकार आयी है अमेरिकी विदेशी नीति बेहद बुरी तरीके से यूटर्न ली है। दुनिया में इस्लामिक फंडामेंटलिजम के उभार और इस्लाम का पश्चिमी ताकतों पर हमलों के बाद अमेरिका की नीति में व्यापक बदलाव आया था और उस बदलाव के कारण अमेरिकी कूटनीति भारत के निकट दिख रही थी लेकिन जो बिडिन के राष्ट्रपति बनते अमेरिका की कूटनीति में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ने लगा है। अमेरिकी कूटनीति के अध्येताओं का मानना है कि अमेरिकी रणनीतिकार अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रणनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं। वैसे भी अमेरिका को दुनिया में कोई ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष नहीं चाहिए। उन्हें तो उनकी नीतियों को अपने देश में लागू करने वाला कमजोर नेतृत्व चाहिए। नरेन्द्र मोदी प्रशासन ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। इन फैसलों में रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार और ब्रिक्स देशों के संबंधों में गर्माहट बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के फैसलों से अमेरिका अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। इस पर से नरेन्द्र मोदी ने रूस-यूक्रेन गतिरोध में तटस्थ रहकर अमेरिका को और ज्यादा असहज कर दिया है। इसके कारण अमेरिका अपने तरीके से मोदी प्रशासन पर नकेल कसने की रणनीति को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया है।

अमेरिका की कूटनीतिक बदलाव का भारत में दो तरह से प्रभाव पड़ रहा है। एक भारत के अंदर जो अमेरिकी लॉबी है वह नरेन्द्र मोदी के खिलाफ दो-दो हाथ करने के लिए सज्ज होने लगे हैं। यही नहीं किसी जमाने में अमेरिका ने जिस आतंकवादी संगठनों को भारत के खिलाफ खड़ा किया उसे फिर से वह सहयोग करना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा अमेरिका अपने यहां फल-फूल रहे कथित मानवाधिकार संगठनों को भारत के खिलाफ प्रचार करने का मंच प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे ही संगठनों में से एक भारतीय-अमेरिकी मुस्लिम परिषद आईएएमसी है। इस संगठन का अमेरिका में बसने वाले भारतीय मुसलमानों के हित से कुछ भी लेना-देना नहीं है। यह संगठन केवल और केवल अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधि को अंजाम देता है। यही नहीं इस संगठन के जानने वालों का तो यहां तक कहना है कि इस संगठन की नींव 2002 के गुजरात दंगे के बाद पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई ने अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए के सहयोग से करवाई थी। इस संस्था का काम ही दुनिया में भारत के खिलाफ प्रचार करना है। विगत कई वर्षों तक यह संस्था बेहद कमजोर परी थी लेकिन विगत दो वर्षों से यह एकाएक सक्रिय हो गयी है। इसके पीछे के होतु को भी समझना चाहिए।

अभी बीते वर्ष यानी 2022 में इस संस्था की ओर से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। भारतीय-अमेरिकी मुस्लिम परिषद आईएएमसी ने अगस्त-सितंबर 2022 में एस्लिंग लिंच केली की एक ऑनलाइन रिपोर्ट ''स्टेट ऑफ रिलिजेंस माइनॉरिटी इन इंडिया'' को प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में ईसाई एवं मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा और हिंसा की प्रवृत्ति बुरी तरह बढ़ती रही है। लेखक ने, अपने दावे को सही ठहराने के लिए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की चिंताओं के बीच कर्नाटक राज्य के धार्मान्तरण विरोधी कानून का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे कानून बहुसंख्यक हिन्दू और अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के बीच तनाव को बढ़ाएगा। रिपोर्ट में आगे एक घटना का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 6 दलित ईसाई महिलाओं को जबरन धार्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो एक हिन्दूवादी संगठन विश्व हिन्दू परिषद के के आरोप पर की गयी कारवाई है। दाखिल आरोप पत्र में बताया गया है कि वे महिलाएं एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान लोगों को जबरन धर्मान्तरित कर रही थी। इसी तरह, लेखक ने यूनाइटेड क्रिश्चन फोरम यूसीएफ का हवाला देते हुए बताया है कि जनवरी से जुलाई 2022 तक ईसाइयों पर 300 से अधिक हमले हुए, जो कि तथ्यों की जांच किए बिना, झूठे, मनगढंत और अतिरंजित आख्यानों पर आधारित है।

इस सब को देखकर यह प्रतीत होता है कि आईएएमसी द्वारा फैलाई गयी यह धारणा, भारत को बदनाम करने की सूनियोजित चाल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल करने का षडयंत्र है। इस संगठन ने भारत में ईसाइयों के उत्पीड़ण के बारे में अपने दावों का समर्थन करने के लिए अतिरंजित एवं अतिशयोक्तिक आकड़ों का उपयोग किया है। जहां तक कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून की बात है तो यह कानून ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रलोभन, जबर्दस्ती, अनुचित प्रभाव और धोखाधरी के माध्यम से बढ़ती धर्मांतरण गतिविधियों को रोकने के लिए शासन द्वारा अधिनियमित किया गया है। आईएएमसी ने अपनी रिपोर्ट में बिना किसी वैध आधार के सरकार की आलोचना की। संभवत: ईसाइयों को यह आशंका हो सकती है कि धर्मांतरण विरोधी कानून, विशेष रूप से उनके समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है लेकिन यह अवधारणा ही गलत है। सत्य तो यह है कि यह कानून जितना हिन्दुओं या मुसलमानों के हित में है उतना ही ईसाइयों के हित में भी है। यदि कोई हिन्दू नेता या संगठन किसी ईसाई को छल-बल से हिन्दू बनाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी वही कारवाई होगी जो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ होगी। रिपोर्ट में इस तथ्य को जानबूझ कर छिपाया गया है कि पुलिस उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए हिन्दुओं सहित दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज किए।

जिला आजमगढ़ में इसी तरह के एक और घटनाक्रम के संबंध में, पुलिस पीएस महाराजगंज ने धारा तीन और पांच 1 के तहत 6 ईसाइयों के खिलाफ गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंतर्गत मामला दर्ज किया, जो न केवल धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल पाये गये बल्कि हिन्दू धर्म एवं हिन्दू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। एर्स्लिच केली की रिपोर्ट, आईएएमसी के निरंतर भारत को दोषी ठहराने के इरादों पर सवालिया निशान लगाती है। आईएएमसी को अपने और पाकिस्तान के बीच कनेक्शन से छुटकारा पाने की जरूरत है और संगठन को वैश्विक स्वीकार्यता चाहिए तो कुछ विश्वसनीयता हासिल करनी होगी। ऐसे में संगठन को भारत को बदनाम करने से बचना चाहिए। इसके लगातार प्रयासों के बावजूद भी यह भारत की छवि को धूमिल नहीं कर पाया है। भारत, अपनी धर्मनिर्पेक्ष साख के लिए विश्व भर में जाना जाता है। भारत का अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय विशेष रूप से अल्पयंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम दे रहा है, जो भारत के धर्मनिर्पेक्ष एवं कल्याणकारी होने का सबूत देते हैं। यही नहीं यह आईएएमसी के द्वारा गढ़े गए अल्पसंख्यक विरोधी आख्यानों को पूरी तरह से खारिज भी करता है।

हरित ऊर्जा का दोहन कर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार की अनुकरणीय पहल

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य की विशाल ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने, विकसित करने और दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य की कुल चिन्हित जलविद्युत क्षमता लगभग 27,436 मेगावाट और दोहन योग्य विद्युत क्षमता 23,750 मेगावाट है, जिसमें से 10,781.88 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार वर्ष 2025 के अंत तक जलविद्युत, हाइड्रोजन व सौर ऊर्जा का दोहन करके प्रदेश को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में राज्य सरकार ने अनुकरणीय पहल की है। इससे न केवल राज्य को हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश हरित उत्पादों की ओर उन्मुख होगा जो राज्य के निर्यात में प्रीमियम और लाभ को बढ़ाएंगे।

वर्तमान प्रणाली का नवीनीकरण और राज्य के विकास के दृष्टिगत हरित ऊर्जा का दोहन अति-आवश्यक है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को वर्तमान ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने और पांच मैगावाट क्षमता तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश भी करेगी।

वर्ष 2023-2024 की अवधि के दौरान प्रदेश भर में 500 मैगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिसमें कम से कम 200 मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड (एचपीपीसीएल) द्वारा स्थापित की जाएंगी। इसके दृष्टिगत 70 मैगावाट क्षमता के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है और अन्य स्थलों को भी शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

150 मैगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं निजी भागीदारी से हिमऊर्जा द्वारा स्थापित की जाएंगी और इन परियोजनाओं के आवंटन में हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन परियोजनाओं की क्षमता की श्रेणी 250 किलोवाट से एक मैगावाट होगी।

प्रदेश सरकार ने हिमऊर्जा को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए है जिसमें 3 मैगावाट क्षमता से अधिक की सौर परियोजनाओं में राज्य को रॉयल्टी प्राप्त होने से वित्तीय लाभ मिल सकें। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान की जाती है तो इसके लिए उनसे भूमि की हिस्सेदारी के रूप में कुछ प्रतिशत राशि भी ली जानी चाहिए।

हिमऊर्जा को पांच मैगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में राज्य के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम और पांच मैगावाट क्षमता से अधिक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 10 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड को काशंग द्वितीय और तृतीय, शॉंग-टांग व कड़छम आदि निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रदेश के लोग इनसे शीघ्र लाभान्वित हो सकें। प्रत्येक परियोजना के लिए समयावधि निश्चित करने और इन सभी परियोजनाओं को वर्ष 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने एचपीपीसीएल को सौर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए 10 दिन के भीतर सलाहकार नियुक्त करने तथा एक माह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है ताकि इन सौर परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किया जा सके। ऊर्जा विभाग तथा एचपीपीसीएल अन्य राज्यों जैसे राजस्थान में भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जहां मैगा सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध है।

प्रदेश को देशभर में हरित ऊर्जा राज्य का मुकाम हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करने में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) का सहयोग संबल प्रदान करेगा। एसजेवीएनएल ने विद्युत उत्पादन क्षेत्र में बेंचमार्क स्थापित किया है और एसजेवीएनएल की संयंत्र का उपलब्धता कारक देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार एसजेवीएनएल की आगामी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने में हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि एसजेवीएनएल की विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा हिस्सेदारी बढ़ाई जाए।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1055 करोड़ रुपये के इक्विटी योगदान की एवज में 2355 करोड़ रुपये की लाभांश आय प्राप्त की है और नाथपा झाकड़ी व रामपुर जल विद्युत परियोजनाओं से 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त की है जिससे अभी तक लगभग 7000 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन (एनजेएचपीएस) से बस-बार दर पर लगभग 4200 करोड़ रुपये की 22 प्रतिशत अतिरिक्त विद्युत भी प्राप्त हुई है।

एसजेवीएनएल की हिमाचल प्रदेश में पांच सौर ऊर्जा परियोजनाएं (एसपीपी) प्रस्तावित हैं। जिला ऊना में 112.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना (एसपीपी) थपलान स्थापित की जा रही है। इसके अलावा ऊना जिला में 20 मेगावाट क्षमता की एसपीपी भंजाल और कध, कांगड़ा जिला के फतेहपुर में 20 मेगावाट, सिरमौर जिला में 30 मेगावाट एसपीपी कोलार और कांगड़ा जिला के राजगीर में 12.5 मेगावाट क्षमता एसपीपी की परियोजनाएं पूर्व-निर्माण चरण में हैं।

प्रदेश सरकार ने आश्वस्त किया है कि निष्पादन एजैंसी को इन परियोजनाओं को निर्माण के लिए वह हर संभव सहयोग प्रदान करेगी तथा कंपनी को सुविधा प्रदान करने के लिए फ्री होल्ड निजी भूमि की खरीद के लिए नीति में संशोधन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार की योजना आगामी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत तक बढ़ाने की है। इन विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा ताकि इन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके।

सोशल मीडिया पर असर डालने वाली हस्तियों के लिए 'एंडोर्समेंट नो-हाउ!' नाम से दिशा निर्देश जारी

शिमला। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता कार्य विभाग ने प्रसिद्ध लोगों, प्रभावशाली व्यक्तियों और सोशल मीडिया पर असर डालने वाली जानी-मानी हस्तियों के लिए डालने वाली जानी-मानी हस्तियों के प्रभाव में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन व्यक्तियों द्वारा विज्ञापनों के प्रचार और अनुचित व्यापार प्रणालियों से उपभोक्ताओं के गुमराह होने का खतरा बढ़ गया है।

'एंडोर्समेंट नो-हाउ!' नाम से दिशानिर्देश जारी किये हैं। इस दिशा निर्देशिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन करते समय अपने श्रोताओं एवं दर्शकों को गुमराह न करें और विज्ञापन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा किसी भी अन्य संबंधित नियम या दिशानिर्देशों के अनुपालन में ही प्रदर्शित हों।

उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने 'एंडोर्समेंट नो-हाउ!' दिशा निर्देशिका जारी की है, क्योंकि तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया के लिए विज्ञापन अब प्रिंट, टेलीविजन या रेडियो जैसे पारंपरिक मीडिया तक ही सीमित नहीं रह गए हैं और ऐसे में नियमों का स्पष्ट होना आवश्यक है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच के साथ ही प्रसिद्ध लोगों, प्रभावशाली व्यक्तियों और सोशल मीडिया पर असर

'एंडोर्समेंट नो-हाउ!' दिशा निर्देशिका यह निर्दिष्ट करती है कि किसी भी विज्ञापन में स्पष्टीकरण को प्रमुखता से और साफ-साफ शब्दों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें याद करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कोई भी प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, प्रभावशाली व्यक्ति और सोशल मीडिया पर असर डालने वाले जानी-मानी हस्ती, जिसकी उपभोक्ताओं तक अधिक पहुंच है और वह किसी उत्पाद, सेवा, ब्रांड या अनुभव के बारे में उनके क्रय निर्णयों या विचारों को प्रभावित कर सकता है, तो उसे विज्ञापनदाता के साथ किसी भी अपने भौतिक संबंध का खुलासा करना चाहिए। इसमें न केवल लाभ और प्रोत्साहन शामिल हैं, बल्कि मौद्रिक या अन्य फायदे, यात्राएं अथवा होटल में ठहरने, मीडिया बार्टर्स, कवरेज तथा पुरस्कार, शर्तों के साथ या बिना मुफ्त उत्पाद, छूट, उपहार और कोई भी पारिवारिक या व्यक्तिगत अथवा रोजगार संबंध शामिल हैं।

विज्ञापन सरल, स्पष्ट भाषा में किया जाना चाहिए और किसी भी उत्पाद के प्रचार के लिए 'विज्ञापन', 'प्रायोजित' या 'सशुल्क प्रचार' शब्द का उपयोग किया जा सकता है। उन्हें ऐसे किसी भी उत्पाद या सेवा और कार्य का विज्ञापन नहीं करना चाहिए, जिसमें मूल बातों को उनके द्वारा उचित तरीके से व्यक्त न किया गया हो या जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल अथवा अनुभव नहीं किया हो।

दिशा निर्देशिका को 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। अधिनियम ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों और भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। उपभोक्ता कार्य विभाग ने 9 जून 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए प्रचार- 2022 के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। ये दिशानिर्देश वैध विज्ञापनों के मानदंड और निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं तथा विज्ञापन एजेंसियों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं। इन दिशानिर्देशों ने मशहूर हस्तियों और विज्ञापन बनाने वालों के लिए निर्देश स्पष्ट किये हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी रूप, प्रारूप या माध्यम में भ्रामक विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

दिशानिर्देश जारी करने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल मीडिया पर असर डालने वाली कई जानी-मानी हस्तियों और एजेंसियों ने भाग लिया। उद्योग जगत ने इन दिशानिर्देशों को जारी करने की सराहना की और समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग को और मजबूती मिलेगी तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा होगी।

युवाओं के भविष्य को संवारने में जुटी प्रदेश सरकार

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बहुआयामी प्रयास आरंभ कर दिए हैं। बात स्कूली स्तर से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तथा आधारभूत ढांचे के सृजन की हो या गुणात्मक शिक्षा की, मुख्यमंत्री ने शिक्षा के हर आयाम को सशक्त करने की विस्तृत योजना तैयार की है।

शिक्षा क्षेत्र को संबल प्रदान करने के लिए पाठयक्रम, तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी और खेलों का समायोजन भी किया जाएगा। छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने व उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। इन स्कूलों में वह हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी जो वर्तमान में उच्च स्तरीय निजी स्कूलों में उपलब्ध करवाई जा रही है। इन स्कूलों में छात्रों को शिक्षा, भाषा, खेल और अन्य क्षेत्रें में निपुण बनाने के लिए बहुआयामी शैक्षणिक ढांचे का सृजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री छात्रों को खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने खेल और शिक्षा का समायोजन करने की योजना बनाई है। राज्य में निकट भविष्य में खेल स्कूल और खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। जहां छात्रों को खेलों के क्षेत्र में भविष्य संवारने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने इस योजना को धरातल पर स्वरूप प्रदान करने के लिए कार्य भी आरंभ कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बावजूद बहुत से स्कूलों में अध्यापकों व अन्य स्टाफ की उपलब्धता आवश्यकता अनुरूप नहीं है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने स्टाफ का युक्तिकरण करने का निर्णय लिया है। शिक्षा क्षेत्र में यह क्रांतिकारी बदलाव निश्चित तौर पर सरकार की योजनाओं और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होंगे।

सरकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उद्योग और अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के साधनों से भलीभांति परिचित है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए तकनीकी शिक्षा को भी विशेष अधिमान देने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। तकनीकी शिक्षा बदलते दौर का सबसे अहम अंग है। तकनीक वैश्विक स्तर पर रोजगार मुहैया करवाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। इसलिए सरकार की योजना है कि व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संबंधित पाठयक्रमों को शामिल किया जाये ताकि सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल तकनीक के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ढूंढ रहे युवाओं को इस क्षेत्र में भी अपना कॅरियर संवारने के अवसर प्राप्त हो सकें।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के उन बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए भी वचनबद्ध हैं जो अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अपना सपन पूरा नहीं कर पाते। सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए 101 करोड़ रुपए की धनराशि से मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। इस कोष के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईआईटी, एनआईटी, आईआईटी, आईआईएम, बहुतकनीकी संस्थानों, नर्सिंग, स्नातक महाविद्यालयों आदि में ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास शिक्षा पर होने वाले व्यय को प्रदेश सरकार वहन करेगी।

प्रदेश सरकार के ये नवोन्मेषी प्रयास निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को देशभर में मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्ती भूमिका अदा करेंगे।

एकता और सौहार्द का संदेश देने के उद्देश्य से आरम्भ की भारत जोड़ो यात्राःराहुल गांधी

शिमला/शैल। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मानसर में प्रवेश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा

सिंह, मंत्रिमण्डल के सदस्यों और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भव्य स्वागत किया।

हिमाचल के सीमावर्ती गांव घटोटा में हिमाचल प्रदेश आगमन पर राहुल गांधी की उपस्थिति में पंजाब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजा वारिंग ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह को तिरंगा सौंपा। भारत जोड़ो यात्रा कांगड़ा जिला के इन्दौरा क्षेत्र के मानसर टॉल प्लाजा से मलोट गांव तक लगभग 24 किलोमीटर पैदल यात्रा तय कर 19 जनवरी, 2023 को जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करेगी। हजारों लोगों एवं समर्थकों ने राहुल गांधी का प्रदेश में पहुंचने पर स्वागत किया और यात्रा में पूरे उत्साह एवं जोश से भाग लिया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस 3570 किलोमीटर की यात्रा का नेतृत्व कर पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन में उमंग एवं नया जोश भर रहे हैं। यह यात्रा 7 सितम्बर, 2022 को तमिलनाडू के कन्याकुमारी से आरम्भ हुई और 30 जनवरी, 2023 को श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ सम्पन्न होगी।

इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आरम्भ करने का उद्देश्य देश में एकता और सौहार्द का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि लगभग चार माह पूर्व कन्याकुमारी से शुरू की गयी यह यात्रा भाजपा व आरएसएस की नफरत वाली विचारधारा के विरुद्ध है। इसके साथ-साथ यात्रा के माध्यम से सरकार को बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के प्रति आगाह भी किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी सारी नीतियां कुछ उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए बना रही है। चाहे नोटबंदी हो या फिर जीएसटी, केंद्र सरकार के फैसले मजदूर, गरीब व आम आदमी के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर मंच पर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष के नेताओं को संसद में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता।

राहुल गांधी ने कहा कि पहले भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित नहीं थी, लेकिन हिमाचलवासियों के स्नेह के कारण यात्रा रूट में बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को पूरे देश में भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है तथा उन्हें भी काफी कुछ सीखने को मिला है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस की भारी जीत भ्रष्टाचार पर सच्चाई की जीत है और इसका श्रेय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्पण और दृढ़ प्रयासों को जाता है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से समस्त हिमाचल कांग्रेस पार्टी द्वारा दिखाए गए एकता और अखण्डता के मार्ग का अनुसरण करेगा।

मुख्यमंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल प्रदेश को शामिल करने के लिए राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया और देवभूमि पधारने पर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच को विचलित किया जा सकता है, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। अंत में जीत सच्चार्ह की होती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में देश की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा शुरू हुई है।

कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में दी गई गारंटियों को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने अपनी पहली ही बैठक में ओपीएस बहाल करने को मंजूरी दे दी है। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह तथा अन्य वायदों को पूरा करने की दिशा में भी सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के लोगों से किया हर वायदा निभाएगी।

इसके उपरांत राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ में पूजा-अर्चना की।

इस अवसर पर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, सह-प्रभारी संजय दत्त, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायकगण, पंजाब कांग्रेस के नेता, भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता तथा अन्य लोग उपस्थित थे।

पंचकर्मा केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यकःहर्षवर्धन चौहान

शिमला/शैल। राज्य के पंचकर्मा केंद्रों को और सुदृढ़ बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किये जाने चाहिए ताकि यह पंचकर्मा उपचार के उत्कृष्ट केंद्र बन सकें। यह बात उद्योग एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए इन केंद्रों में विशेष प्रशिक्षित

स्टॉफ तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों, जैसे परवाणू, पालमपुर, धर्मशाला, मनाली आदि में पंचकर्मा उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे जहां प्रदेश में एक ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर विभाग की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने विभाग को राज्य में एकीकृत वेलनेस केंद्रों के विकास के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए।

आयुष मंत्री ने अधिकारियों को केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पपरोला कांगड़ा को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में परिवर्तित करने के प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं का सदुपयोग करने के लिए वर्तमान में मौजूद मानव संसाधनों का युक्तिकरण किया जाना चाहिए। इसके दृष्टिगत आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में सेवारत स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक अधिकारियों की सेवाएं आयुष अस्पतालों में ली जा सकती हैं।

उन्होंने आयुष विभाग की विभिन्न पहल की सराहना करते हुए राज्य के आयुर्वेदिक औषधालयों को सशक्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की विभिन्न दवा निर्माण इकाइयों में आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि राज्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके और इकाइयां अधिक लाभ भी अर्जित कर सकें।

सचिव, आयुष राजीव शर्मा ने आयुष मंत्री को आश्वस्त किया कि विभाग पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा ताकि यह प्राचीनतम उपचार पद्धति लोगों में और अधिक लोकप्रिय हो सके। निदेशक आयुष विनय सिंह, अतिरिक्त निदेशक ताशी संडुप तथा राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला, कांगड़ा के प्रधानाचार्य डॉ. विजय चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज़ को भोजन का हिस्सा बनाए

शिमला/शैल। इस वर्ष मोटे अनाज़ (मिल्लेट्स) को भोजन का अभिन्न अंग बनाने और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाने का एक शानदार अवसर है। हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान और 'मिल्लेट मैन ऑफ हिमाचल' के नाम से प्रसिद्ध नेक राम शर्मा ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में विद्या भारती के शिक्षकों, जो की विवि के एक दिवसीय भ्रमण पर आए थे, को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए।

सभा को संबोधित करते हुए, नेक राम शर्मा ने कहा कि मोटे अनाज़ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ने मिल्लेट्स के महत्व को सामने लाया है और हमें इस पर जागरूकता बढ़ाने और इन खाद्य पदार्थों को अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करने का एक सुनहरा अवसर दिया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज़ खाने के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी बताया।

कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने इस अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय ने राज्य में मिल्लेट्स के प्रचार के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए एक गतिविधि कैलेंडर बनाया है क्योंकि ये फसलें विश्व की खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने इन सुपरफूड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में एक मिल्लेट्स आधारित व्यंजन शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे इन फसलों को अपने खेतों में उगाए और व्यक्तिगत उपयोग के मिल्लेट्स उत्पादन में शामिल किसानों से उनकी उपज खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित करें।

इससे पहले निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. इंदर देव ने बताया कि 1970 से

पहले मोटे अनाज भोजन का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होता था लेकिन आज यह घटकर केवल 6 प्रतिशत ही रह गया है। स्थायी खाद्य प्रणाली विशेषज्ञ आशीष गुप्ता ने मिल्लेट्स के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बात की और बताया कि कैसे कठोर परिस्थितियों में भी कैसे उगाया जा सकता है।

इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विद्या भारती स्कूलों के 120 से अधिक शिक्षकों और उत्तरकाशी के किसानों, विश्वविद्यालय के वैधानिक अधिकारों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को काँगनी (फॉक्सटेल मिल्लेट्) से बनी खीर भी परोसी गई।

अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु अधिनियम के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीएसपीसीबी) के प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड ने सोलन जिला के बागा में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, बागा की इकाई की पिछले वर्ष स्टैक उत्सर्जन निगरानी की गई थी, और यह पाया गया कि स्टैक उत्सर्जन निगरानी के परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसके बाद, एचपीएसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय ने पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर एपीसीडी के सुचारू संचालन के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए इकाई को नोटिस जारी किया था।

इससे पूर्व इकाई में सीमेंट मिल, रॉ मिल और कोयला मिल में स्टैक उत्सर्जन निगरानी की गई थी जो कि निर्धारित मापदंडों से ऊपर पायी गयी। उन्होंने कहा कि स्टैक उत्सर्जन के उल्लंघन के लिए इकाई के खिलाफ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कारवाई शुरू की गयी थी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कानून का उल्लंघन करने वाली इकाईयों से पर्यावरण नुकसान की भरपाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने कई अवसर प्रदान किए, लेकिन यूनिट अभी भी जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।

अब हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इकाई से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ दंडात्मक कारवाई की जाए और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण नुकसान की भरपाई भी की जाए।

उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है या सात वर्ष तक का कारावास या मामले के अनुसार दोनों का भी प्रावधान है।

प्रवक्ता ने कहा कि इसी प्रकार के एक अन्य मामले में, मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, बागा की परिवेशी वायु और स्टैक उत्सर्जन निगरानी की गयी थी। परिवेशी वायु और स्टैक उत्सर्जन का परिणाम एकत्र किया गया था, जो निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नहीं था। निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि संयंत्र क्षेत्र में पानी के छिड़काव की व्यवस्था नहीं होने और वाहनों की आवाजाही के कारण धूल का उत्सर्जन होने पर एक बार फिर इकाई का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा, कोयला मिल क्षेत्र को शीट कवर भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके परिणामस्वरूप इकाई को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब तैयार करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उप-मुख्यमंत्री ने फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा से भेंट की। उन्होंने

कुशविंदर वोहरा से राज्य की सिंचाई योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के बारे में विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के नूरपुर स्थित फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना वर्ष 2011 में 204 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि से शुरू की गयी थी जो कि अब बढ़कर 646 करोड़ रुपये की हो गयी हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए राज्य ने अपने संसाधनों से अब तक 283 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। उन्होंने केंद्र से अतिरिक्त 350 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का आग्रह किया ताकि परियोजना का कार्य प्राथमिक आधार पर पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता सूची में है।

उन्होंने बताया कि शाह नहर परियोजना के तहत आने वाली 5000 हेक्टेयर भूमि में सिचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नही हो रहा है। उन्होंने इस भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने का आग्रह किया।

मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले के बीट क्षेत्र में 75 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सिंचाई योजना, चरण-दो को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के चरण-एक का कार्य राज्य ने अपने संसाधनों से पूर्ण कर लिया है। उन्होंने बताया कि नादौन सिंचाई योजना का शेष कार्य भी आगामी दो-तीन माह की समयावधि पर पूर्ण कर लिया जाएगा।

उन्होंने केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष को प्रदेश में मौजूदा योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और नई सिंचाई योजनाओं के लिए संभावनाएं तलाशने और कार्यान्वयन बारे में रोडमैप तैयार करने के लिए हिमाचल पधारने के लिए आमंत्रित किया।

इस अवसर पर उन्होंने सुखाहार और ज्वालाजी सिंचाई योजनाओं के बारे में भी आयोग के अध्यक्ष से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने प्रदेश की खड्डों के तटीकरण के लिए वित्तीय प्रबंध बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बाढ़ नियंत्रण उपायों और खड्डों के तटीकरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने प्रदेश को हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वसन दिया।

जेपी नड्डा का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया

शिमला/शैल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा कर जानकारी दी की जगत प्रकाश नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारणी ने प्रस्ताव किया। राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा, सभी भाजपा के सदस्यों ने इसे स्वीकार किया है। जेपी नड्डा को जून 2024 तक के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल, त्रिलोक कपूर, संगठन महामंत्री पवन राणा, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, सतपाल सत्ती, पार्टी के सभी उपाध्यक्षों, सचिव, प्रवक्ता, मीडिया एवं सह मीडिया प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों ने जगत प्रकाश नड्डा को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी।

हिमाचल में सरकार की योजनाओं का नाम बदलना ठीक नहीं: जयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला विधानसभा

में नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला, उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप में उपस्थित रहे। भाजपा पदाधिकारियों एवं भाजपा नेताओं ने उनको इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा अगर कांग्रेस सरकार जनहित में निर्णय नही लेगी तो हम पूरी ताकत के साथ निर्णय का विरोध करेंगे। प्रदेश के विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक और परंपरा शुरू होने जा रही है अब हिमाचल प्रदेश की योजनाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। भारत रतन अटल बिहारी वाजपई के नाम योजनाओं को अब हिमाचल में राजीव गांधी के नाम पर रखा जा रहा है, यह कोई स्वस्थ परंपरा नही है।

विभागीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए नवोन्मेषी विचारों एवं पेशेवर ढंग से कार्य करें:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 'निर्माण भवन' शिमला में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों, नाबार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सी.आर.एफ., हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम सीमित इत्यादि के अंतर्गत जारी विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभागीय अधिकारी अत्याधुनिक तकनीकों का समावेशन करते हुए कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए नवोन्मेषी विचारों एवं पेशेवर ढंग से कार्य करें। उन्होंने कहा कि विभाग की आधारभूत संरचना में सुधार और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना की डीपीआर तैयार करने के साथ ही एफसीए सहित अन्य सभी औपचारिकताएं भी पूर्ण कर लें ताकि परियोजना कार्य को गति प्रदान की जा सके। भूमि की उपलब्धता सहित एफसीए के मामलों में स्थानीय जन प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इनके समयबद्ध निपटारे के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदेश में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को फोरलेनिंग कार्य के दौरान शिमला व सोलन के मध्य कटिंग से होने वाले संभावित भू-स्खलन स्थलों की पहचान करने तथा इसकी रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सड़क मार्ग एक तरह से हिमाचल प्रदेश का गेट-वे है और सैलानियों के लिए यहां आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना विभाग और सरकार की प्राथमिकता है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि शिमला से कांगड़ा एवं मंडी सहित लगभग छः जिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंडल के समीप स्थायी पुल के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए क्योंकि यह मार्ग एक तरह से इन जिलों को राजधानी से जोड़ने वाली लाईफलाइन है। उन्होंने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जारी विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों को भी निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

विद्युत विंग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा निर्मित किए जाने वाले भवनों में सौर ऊर्जा संचालित विद्युत आपूर्ति का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बर्फबारी प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 7500 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं और प्रदेश सरकार ने इन सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। भारी बर्फबारी के कारण बंद हुई सड़कों को शीघ्रातिशीघ्र बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए सामान्य क्षेत्रों से अतिरिक्त मशीनरी इत्यादि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इससे बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बहाल करने में तेजी आयी है और विभाग को किराए पर मशीनरी लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कों के निर्माण, उचित रखरखाव व मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए विभाग को अत्याधुनिक तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और मेरी सड़क, ई-समाधान तथा सीपी ग्राम इत्यादि ऐप के माध्यम से आम जन इस बारे में शिकायतें भी भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा कि विभाग सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। उन्होंने चिन्हित ब्लॉक स्पॉट को दुरुस्त करने के साथ ही अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों पर मरम्मत तथा क्रैश बैरियर इत्यादि लगाने पर भी बल दिया।

बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बैठक की कारवाई का संचालन किया।

बैठक के दौरान शिमला शहर के विकास तथा सड़क सुरक्षा विषय पर प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत की गई।

विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग हरबंस सिंह ब्रसकोन एवं तोरुल एस.रवीश, प्रमुख अभियंता (परियोजना) अर्चना ठाकुर सहित सभी मुख्य अभियंता तथा विभिन्न वृतों के अधीक्षण अभियंता बैठक में उपस्थित थे।

प्रदेश के लोगों को इस वर्ष के अंत तक 5जी सुविधा प्रदान की जाएगी:अभिषेक जैन

शिमला/शैल। सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि प्रदेश के लोगों को इस वर्ष के अंत तक 5जी इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में यहां आयोजित टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर-संचार विभाग व हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के अधिकारियों और डिजिटल आधारभूत संरचना प्रदाता संघ के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के उपरांत यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में दूर-संचार क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा इस सुविधा से वंचित गांवों, कम सिग्नल उपलब्धता वाले क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5जी इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं। दूर-संचार सेवा प्रदाताओं को हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 5जी इंटरनेट सुविधा के उपलब्ध होने से डेटा हस्तांतरण व क्षमता में भी आशातीत बढ़ोतरी होगी। इससे विकास कार्यों को भी नए आयाम प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति समय की मांग है और इससे कार्य करने की दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी।

बैठक में उपस्थित विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों ने आश्वस्त किया कि 5जी सुविधा के लिए आधारभूत ढांचे की स्थापना के दौरान पर्यावरण को कम से कम नुकसान और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत सभी प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में यह सुझाव दिया गया कि सभी सेवा प्रदाता कंपनियों को समन्वय के साथ कार्य कर आधारभूत संरचना स्थापित करने का कार्य एक साथ करना चाहिए ताकि जमीन को बार-बार खोदना न पड़े।

सेवा प्रदाताओं ने 5जी से संबंधित राज्य की नीति में कुछ आवश्यक संशोधन करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे उन्हें सुविधा प्रदान करने में आसानी होगी।

इस अवसर पर डिजिटल आधारभूत संरचना प्रदाता संघ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। डिजिटल आधारभूत संरचना प्रदाताओं को केरल में उनकी पायलट परियोजना से संबंधित रिपोर्ट साझा करने के लिए भी कहा गया।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 5जी सेवा से संबंधित विस्तृत प्रस्तुति भी दी।

विशेष सचिव सूचना प्रौद्योगिकी टी. एस. रवीश, लोक निर्माण, शहरी विकास, राजस्व, विद्युत बोर्ड के अधिकारी और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

25 जनवरी से 15 फरवरी तक जयराम की अगवाई में भाजपा का विरोध प्रदर्शन

सुक्खू सरकार के फैसले रहेंगे निशाने पर
जयराम ने नवम्बर 2021 में घटाये थे डीजल के रेट
इसी दौरान होगी कांग्रेस की “हाथ से हाथ जोड़ो” यात्रा

शिमला/शैल। हिमाचल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद प्रदेश भाजपा में इस हार के लिये कुछ वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहराने का एक अप्रत्यक्ष दौर चला था। इसके संकेत पूर्व मन्त्री सुरेश भारद्वाज, राकेश पठानिया नादौन मण्डल के कथित पत्र और पूर्व मुख्यमन्त्री शान्ता कुमार के ब्यान कि **“भाजपा को भाजपाईयों ने ही हराया है”** से सामने आ गये थे। संभवतः इन्ही संकेतों के आधार पर की नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने भी यह कहा था कि भीतरघातियों के खिलाफ कारवाई होनी ही चाहिये। इसी परिदृश्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुर कुछ लोगों के निशाने पर आ गये थे। यह माना जाने लगा था कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के संभावित फेरबदल में अनुराग ठाकुर के मन्त्री पद पर आंच आने के साथ ही नड्डा के कार्यकाल में विस्तार की संभावना भी खत्म हो जायेगी। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह सब नहीं हुआ। नड्डा को कार्यकाल में एक वर्ष का विस्तार भी मिल गया और अनुराग ठाकुर को उत्तर प्रदेश के प्रभारी की और जिम्मेदारी मिल गयी। पार्टी में घटे इस सबको 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिपेक्ष में देखा जा रहा है। क्योंकि पीछे हुये चुनावों में गुजरात की जीत से ज्यादा हिमाचल और दिल्ली की हार का सन्देश गया है। दिल्ली और हिमाचल के चुनाव प्रदेश के स्थानीय नेताओं से ज्यादा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के चेहरों पर लड़े गये थे। इस हार से भाजपा के इन राष्ट्रीय चेहरों की लोकप्रियता पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगे हैं। क्योंकि भाजपा की यह हार उस समय हुयी है जब कांग्रेस के पास भाजपा की नजर में कोई बड़ा चेहरा प्रदेश में नहीं था। इसलिये यह हार जनता की नाराजगी का सीधा प्रमाण है और यह नाराजगी लगातार बनी हुई है।

इस परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि भाजपा ने हिमाचल में यथास्थिति को ही बनाये रखने में पार्टी के लिये हितकर माना है। इसी हित संरक्षण के तहत पूर्व मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष बने और नड्डा तथा अनुराग की कुर्सियां बची रही। यह सब लोकसभा चुनावों को सामने रखकर किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या इससे सही में भाजपा को चुनाव में लाभ मिल पायेगा। इसका आकलन करने के लिये सरकार और भाजपा की वर्तमान स्थिति पर नजर डालना अवश्य को जाता है। सरकार ने जयराम काल के अंतिम छः माह के फैसले पलटे हैं। भाजपा की ओर से इन फैसलों के खिलाफ दो याचिकाएं प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गयी हैं। इसके बाद सुक्खू सरकार ने छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां करके एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। क्योंकि एक समय प्रदेश उच्च

न्यायालय इन्हें असंवैधानिक करार दे चुका है और उसके बाद बनाया गया अधिनियम भी उच्च न्यायालय में लबित है। लेकिन इसी के साथ सुक्खू सरकार ने डीजल पर तीन रूपये प्रति लीटर वैट बढ़ाकर लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। भाजपा और जयराम ने इस बढ़ौतरी का विरोध करते हुये यह खुलासा किया है कि जयराम की सरकार ने नवम्बर 2021 में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की थी। डीजल के रेट 17 रूपये प्रति लीटर घटाये गये थे। सुक्खू सरकार ने जयराम कार्यकाल में डीजल के घटाये गये दामों को पिछले छः माह में लिया गया फैसला करार देते हुये इसे भी पलटने का काम किया है। ऐसे में अब यह बहस एक रोचक विषय बन जायेगी कि सुक्खू सरकार में नवम्बर 2021 में लिये गये जनलाभ के फैसले को संसाधन जुटाने के नाम पर बदला है और फिर गलत ब्यानी भी की जा रही है।

सुक्खू सरकार के इन फैसलों के खिलाफ भाजपा 25 जनवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर इन प्रदर्शनों की अगुवाई करेंगे। यह प्रदर्शन हर उस स्थान पर किये जायेंगे जहां-जहां यह संस्थान खुले थे और इस सरकार ने बन्द किये हैं। स्वभाविक है कि जो लोग इन फैसलों से प्रभावित हुये हैं वह विरोध में हस्ताक्षर करने से पीछे नहीं हटेंगे। 15 फरवरी तक यह विरोध प्रदर्शन चलेगा और उसके बाद पूरे बजट सत्र में यह मुद्दा गूंजता रहेगा। सरकार और कांग्रेस की ओर से इस विरोध प्रदर्शन का कितना प्रमाणिक जवाब दिया जायेगा यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब **“हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा”** जिस दिन से शुरु करेगी उसी दिन से भाजपा की यह विरोध यात्रा शुरू होगी। भाजपा के पास लोगों में जाने के लिये सरकार के यह फैसले हैं। कांग्रेस और भाजपा इस संयोग में आमने-सामने की स्थिति में आ खड़े होंगे। कांग्रेस का संगठन सुक्खू सरकार के फैसलों की रक्षा जनता में कैसे कर पाता है यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि सत्ता परिवर्तन के बाद बनी सरकार के पहले फैसले पर पहले ही दिन विपक्ष हमलावर हो जाये और उसके मुद्दों में वजन भी हो।

पूर्व जयराम सरकार पर कर्मचारी सेवा महासंघ की मान्यता मामले में घपले का गंभीर आरोप

महासंघ नेता विनोद कुमार ने की जांच की मांग

शिमला/शैल। प्रदेश के कर्मचारी राजनीति को प्रभावित करते हैं यह एक स्थापित सत्य है। इसलिये जब कर्मचारी नेतृत्व किन्ही कारणों से सत्ता के अनुकूल नहीं होता है तब राजनीतिक नेतृत्व प्रशासन के माध्यम से कर्मचारी संगठन ही कैसे तोड़फोड़ का जाल बुनते हैं इसका खुलासा कर्मचारी नेता विनोद कुमार द्वारा सुक्खू सरकार को भेजी शिकायत से सामने आया है। विनोद कुमार ने इस पर सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

यह है शिकायत

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ
(हि0 प्र0 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)
NON-GAZETTED SERVICES FEDERATION
(Recognized by H.P. Govt.)

Vinod Kumar
President
Email: vk275101@gmail.com
94181-20088 (M)

Ashwani Kumar Sharma
Sr. Vice President

Gitesh Prashar
Secretary General
98162-94099 (M)

दि: 20.1.2023

विषय: हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाऐं महासंघ की मान्यता पर पूर्व भाजपा सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारी संगठन के साथ किए गए छलकपट–घोटाले की जांच बारे आग्रह।

माान्यवर मुख्यमंत्री महोदय,

“जय हिन्द”

आपके नेतृत्व में गठित नई सरकार पर आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाऐं और बधाई। महोदय, सत्ता संभालने पर आपने जिस प्रकार स्वच्छ–पारदर्शी शासन देने का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है, निश्चित रुप से आपकी यह दूरदर्शिता प्रदेश के आम जनमानस और व्यवस्था के लिए एक नई किरण है। आपके नेतृत्व में पिछले एक महीने में आपके सभी निर्णय प्रदेश के हर वर्ग में आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण की पुष्टि है।

मान्यवर, महोदय महासंघ आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता है कि आपकी सरकार की शून्य भ्रष्टाचार नीति और व्यवस्था परिवर्तन के लिए साहसिक फैसले लिए जा रहे हैं, उसी ही कड़ी में कर्मचारी संगठन की राजनीति में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाऐं महासंघ के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा लिया गया गैर– जिम्मेदाराना निर्णय और इस घोटाले की जांच/ समीक्षा का निवेदन है, ताकि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए इस प्रशासनिक घोटाले की सच्चाई प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पता चल सके। चूंकि यह इस लिए भी जरुरी है कि कार्यालयों का वातावरण एवं कार्य संस्कृति गुटबाजी की भेंट न चढ़े और कर्मचारी संगठन की राजनीति सरकार और कर्मचारियों के वर्ग के बीच एक कड़ी के रुप में कार्य कर सके।

–2–

–2–

मान्यवर, महोदय 1960 के दशक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु जी ने देश के कर्मचारियों के लिए केबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में ज्वांइट कन्सलटेटिव मशीनरी का गठन किया गया था, और उसी ही तर्ज पर 1979 में हिमाचल प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शांताकुमार जी ने ज्वांईट कन्सलटेटिव कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारियों के लिए गठित की थी ताकि तय नियमों / प्रकियाओं के आधार पर कर्मचारी सेवाऐं मसलों पर सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच उचित चर्चा कर उनका समाधान/ निराकरण समय समय पर होता रहे।

महोदय पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कर्मचारी संगठन और जे सी सी की मान्यता के मूल मापदण्डों पर प्रहार कर अपनी व्यक्तिगत निष्ठाओं को तरजीह देकर क्षेत्राविशेष के एक शिक्षा विभाग से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारी को महासंघ की मान्यता के नाम पर जे सी सी के लिए वुलाने का फरमान पत्र संख्या पी ई आर (एपी)–C-F(4)-1/2018-एल, दिनांक 20.07.2021 को जारी कर दिया गया, जिसके कारण पूरे प्रदेश का कर्मचारी सरकार के इस घोटाले/ धोखे से स्तब्ध रह गया। पूर्व सरकार के इस फैसले का विरोध मिडिया, ज्ञापनों और कानूनी नोटिस के जरिए कर इस अलोकतांत्रिक/असंगत कार्रवाई को वापिस लेने की मांग की गई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने चहेतों के लिए किए गए इस घोटाले को कर्मचारियों के प्रति अपनी घृणात्मक विरोधी सोच पर ही मुहर लगा दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश के कर्मचारियों ने 2021 के उप चुनाव में ही जयराम सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कर दिया था।

महोदय, निवेदन है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच करने की कृपा करे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने महासंघ के संविधान के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों के बहुमत और सरकार के निर्धारित मापदण्डों/ नियमावली के एकदम उल्ट जाकर कार्मिक विभाग से कथित महासंघ के नाम 20.07.2021 को जो पत्र जारी किया गया वह गैर जिम्मेदाराना और असंगत कार्रवाई थी। महासंघ के साथ जेसीसी की मान्यता बारे जुलाई 2019 से सरकार के कार्मिक विभाग ने इस पूरे मामले को मूल नस्ति पर डील किया गया है और जो अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में चुनाव की प्रोसीडिंग और अन्य पत्राचार इस सम्बन्ध में सरकार से किए गए हैं उस पर कार्मिक विभाग से क्या निर्णय कार्रवाई हुई है, जबकि अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में कर्मचारी महासंघ की असली निर्वाचित कार्यकारणी ने सरकार से विभिन्न स्तरों पर जे सी सी की मांग और अन्य मसले उठाए जाते रहे हैं। महोदय सरकार से निवेदन है कि पूर्व मुख्यमंत्री के इस अनैतिक निर्णय पर सरकार शीघ्र जांच कर फैसला ले ताकि राज्य के कर्मियों में भ्रम की स्थिति खत्म हो और महासंघ का

–3–

–3–

आगामी चुनाव उस कार्यकारणी की अधिसूचना जारी कर किया जा सके। चूंकि यह इसलिए भी आवश्यक है कि कर्मचारी व्यवस्था का स्थाई हिस्सा है और ऐसी भ्रम की स्थिति में कर्मचारी वर्ग सरकार के प्रति जहां अविश्वास की स्थिति में रहता है वहीं कर्मचारी वर्ग में पूर्व सरकार का ऐसा व्यवहार अनैतिक कार्यों को बढ़ावा देने वाला रहा है। जिस पर रोक लगाने की नितांत आवश्यकता है ताकि माननीय मुख्यमंत्री का व्यवस्था परिवर्तन का दृष्टिकोण सही अर्थों में सफल हो सके। 2019 से महासंघ के इस मामले पर जो सरकार से पत्राचार हुआ है, उसके कुछ दस्तावेज अवलोकनार्थ पुनः संलग्न हैं:–

1. चुनाव कार्यवाही दिनांक 21.07.2019
2. चुनाव अधिसूचना दिनांक 23.07.2019
3. पत्र दिनांक 03.10.2019
4. पत्र दिनांक 25.10.2019
5. पत्र दिनांक 22.08.2019
6. पत्र दिनांक 23.01.2020
7. पत्र नोटिफिकेशन संदर्भ 09.08.2021
8. कानूनी नोटिस 24.07.2021
9. पत्र दिनांक 05.12.2022

सेवा में
माननीय मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला–2

भवत सद्भवी
विनोद कुमार
20.01.2023
प्रदेशाध्यक्ष
मार्फत निदेशालय उद्यान
नवबहार, शिमला–2

विनोद शर्मा
महासचिव, NGO Service fed.
जिला शिमला एवं
प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचन विभाग
संगठन, हि0प्र0।

(Govind Singh Bhagla)
President
Distt. NGO's Fed. Shimla